इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 01 जून 2018

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू सहायकों का पंजीकरण न करने वाले राज्यों को ग्रांट न देने का निर्देश दिया:

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू सहायकों को पंजीकृत नहीं करने वाले राज्यों को किसी भी प्रकार की ग्रांट मंजूर न करे। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ राज्यों ने उसके विगत 11 जनवरी के आदेश का संकलन तक नहीं किया है।
- उस आदेश में फरवरी से घरेलू सहायकों का पंजीकरण शुरू करने को कहा गया था। बतौर पायलट प्रोजेक्ट उसने पहले दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से घरेलू सहायकों का पंजीकरण करने को कहा था।
- अदालत ने केंद्र सरकार को यह निर्देश एनजीओ श्रमजीवी महिला समिति की याचिका पर दिया है।

बाल अश्लीलता के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए पोर्टल स्थापित किया गया:

- गृह मंत्रालय ने 31 मई 2018 को बाल अश्लीलता (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) और बलात्कार / गैंगरेप (सीपी / आरजीआर) कंटेंट से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल www.cyberpolice.gov.in और हेल्पलाइन नंबर '155260' लॉन्च किया।
- मंत्रालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि वो राज्य पुलिस मुख्यालय में नोडल साइबर सेल स्थापित करें, 15 जून तक ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों / सामग्री को संभालने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें, समय पर ऐसी शिकायतों की जांच करें और नेट से किसी भी बाल अश्लीलता / बलात्कार वीडियो सामग्री को तुरंत हटा दें / ब्लॉक करें।

भारत सरकार और विश्व बैंक में 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए समझौता:

- भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़क परियोजना को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए समझौता हुआ।

इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 01 जून 2018

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना के अंतर्गत 7,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जानी हैं, जिसमें से 3,500 किलोमीटर का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया जाएगा।
- विश्व बैंक वर्ष 2004 में शुरुआत से ही पीएमजीएसवाई को सहयोग दे रहा है। अभी तक इसके तहत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमजोर और पहाड़ी राज्यों में 180 करोड़ डॉलर के कर्ज के माध्यम से निवेश किया जा चुका है।
- इसके अंतर्गत लगभग 35,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सुधार किया जा चुका है, जिससे लगभग 80 लाख लोगों को फायदा हुआ है।

भारत में तंबाकू धूम्रपान करने में तेज गिरावट आई है: डब्ल्यूएचओ

- 31 मई 2018 को जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2000 के 19 .4% की तुलना में भारत में तंबाकू धूम्रपान का प्रसार 2005 में घटकर 11.5% हो गया।
- रिपोर्ट में इस प्रसार के 2020 तक 9.8% और 2025 तक 8.5% तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि रिपोर्ट में केवल धूम्रपान के रूप में तम्बाकू के उपयोग को शामिल किया गया है, जबकि भारत में चबाने वाली तंबाकू के उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी आबादी है, जिससे अतिरिक्त बोझ पैदा होता है।
- धूम्रपान प्रसार में गिरावट की यह रिपोर्ट ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस) के परिणाम के साथ समन्वयित है।

8 नए राज्यों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू होगा:

- राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 जून 2018 से पंजाब और ओडिशा समेत छह राज्यों में लागू हो जाएगी।
- छह राज्यों- मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा और जम्मू-कश्मीर में एक जून से राज्य के अंदर माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू होने जा रही है। इसके अलावा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ई-वे बिल प्रणाली क्रमश: 2 और 3 जून से लागू होगी।

1000+ TESTS FOR 1 YEAR
SSC | BANKING | RAILWAY | STATE EXAMS
Join Tyari PLUS
Rs. 399 Only

इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 01 जून 2018

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पहले ही कह चुका है कि राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल 3 जून से अनिवार्य होगा।
- अभी तक 27 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में आठ लाख ई-वे बिल निकाले गए थे, 30 मई तक इन बिलों की संख्या बढ़कर औसतन 16.8 लाख हो गई है। जीएसटीएन ने कहा कि ई-वे पोर्टल पर अब तक कुल 6.43 करोड़ ई-वे बिल निकाले जा चुके हैं।

वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर 7.7% हुई:

- वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर 7.7% हो गई है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जनवरी-मार्च तिमाही में 7.7 फीसदी रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6.1% थी।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2017-18 की बाकी तीनों तिमाहियों से बेहतर ग्रोथ रेट चौथी तिमाही में आया है। वहीं वर्ष 2017- 18 में आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़कर 6.7% रही।

डेनमार्क ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबन्ध लगाया:

- डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर पूरे चेहरे पर इस्लामी नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश की संसद ने 31 मई 2018 को इससे जुड़ा कानून पारित किया। इसके साथ ही डेनमार्क इस तरह की रोक लगाने वाला यूरोप का सबसे नया देश बन गया।
- संसद में कानून के पक्ष में 75 जबकि विपक्ष में 30 वोट डाले गए। सरकार द्वारा पेश किए गए कानून का सोशल डेमोक्रेट्स और घोर दक्षिणपंथी डैनिश पीपुल्स पार्टी ने भी समर्थन किया। कानून एक अगस्त को प्रभाव में आ जाएगा।
- कानून के तहत सार्वजनिक स्थल पर बुर्का या नकाब पहनने पर 1,000 क्रोनर (156 डॉलर, 134 यूरो) का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 क्रोनर तक का जुर्माना लगेगा।

1000+ TESTS FOR 1 YEAR
SSC | BANKING | RAILWAY | STATE EXAMS
Join Tyari PLUS
Rs. 399 Only

इवनिंग न्यूज़ डाइजेस्ट: 01 जून 2018

'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट' का सफल उड़ान परीक्षण:

- 'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर)' प्रणोदन आधारित मिसाइल का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उड़ान परीक्षण आईटीआर, चांदीपुर, उड़ीसा के लॉन्च सेंटर-3 से सफलतापूर्वक किया गया है।
- इस उड़ान परीक्षण ने मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया। इस परीक्षण के माध्यम से नोजल के बिना बूस्टर की तकनीक को देश में पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।
- एसएफडीआर परंपरागत ठोस ईंधन या तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में एक अलग प्रकार की प्रणोदन तकनीक है।

हरियाणा हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर खोलेगा:

- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के शेष 15 जिलों में अतिरिक्त 15 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में सात जिलों नामत: करनाल, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी और नारनौल में सात ओएससी संचालित हैं।
- इन केंद्रों का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता एवं परामर्श और पांच दिनों के लिए अस्थायी प्रवास जैसी एकीकृत सुविधाएं प्रदान करना है।
- वन स्टॉप सेंटर निर्भया फंड के तहत एक शत-प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना है।

1000+ TESTS FOR 1 YEAR
SSC | BANKING | RAILWAY | STATE EXAMS
Join Tyari PLUS
Rs. 399 Only

क्या आप इस प्रकार के परीक्षा–केंद्रित करेंट अफेयर्स और पढ़ने के इच्छुक हैं?

तो लगाएं अपने इंतजार पर पूर्ण विराम!

पाएं 15% छूट

कूपन कोड : **PDF15**

399 रुपये में ज्वाइन करें TyariPLUS और पाएं

- सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, राज्य परीक्षा आदि के मॉक टेस्ट के लिए 12 महीने तक का सम्पूर्ण एक्सेस
- मासिक करंट अफेयर्स पीडीएफ के लिए 12 महीने तक का सम्पूर्ण एक्सेस
- परीक्षा विशेषज्ञों से परामर्श और डाउट क्लीयरेन्स सेशन
- एप्प में विज्ञापन रहित रीडिंग अनुभव

TyariPLUS